

HM  
न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा०मधु खरे

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3742-तीन/2015 - विरुद्ध आदेश दिनांक  
28-5-2014 - पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी  
- प्रकरण क्रमांक 109/2013-14 स्वमेव निगरानी

भूपेन्द्र सिंह पुत्र लाल साहव नंदवंशी

निवासी ग्राम एजवारा

तहसील बदरवास जिला शिवपुरी

---आवेदक

विरुद्ध

म०प्र०शासन

--अनावेदक

(श्री एम०पी०बरुआ अभिभाषक - आवेदक)

(श्री अनिल श्रीवास्तव अभिभाषक - अनावेदक )

आ दे श

(दिनांक 23 दिसम्बर, 2015)

अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक  
109/2013-14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक  
26-5-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की  
धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी दिनांक 17-11-2015 को  
प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि शासकीय पट्टेदारों की भूमियां  
कलेक्टर की बिना अनुमति के विक्रय वावत् गठित जांच समिति की

01

30/11/15

रिपोर्ट पर ग्राम मझारी स्थित भूदान बोर्ड के पट्टे की भूमि सर्वे क्रमांक 548 रकबा 0.67 है., 555 रकबा 0.06 है., 556 रकबा 0.02 है., 557 रकबा 0.03 है. , 561 रकबा 0.09 है. , 610 रकबा 0.91 है. कुल किता 6 कुल रकबा 1.78 हैक्टर हीरा पुत्र मुतिया जाटव के नाम थी, जिसका विक्रय कलेक्टर शिवपुरी की अनुमति के बिना आवेदक के हित में पाये जाने से अपर कलेक्टर शिवपुरी ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 109/2013-14 दर्ज कर हीरा पुत्र मुतिया जाटव पट्टाग्रहीता को एवं आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाबजूद सूचना पट्टेदार तथा क्रेता आवेदक नियत पेशी 10-10-13 को अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। अपर कलेक्टर शिवपुरी ने अनुविभागीय अधिकारी कोलारस से प्रतिवेदन दिनांक 4.3.2013 प्राप्त कर आदेश दिनांक 22-5-2014 पारित किया एवं पट्टेदार की भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय होना पाकर पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का पालन न करने से संहिता की धारा 165 के अंतर्गत विक्रय पत्र शून्य घोषित करते हुये भूमि शासकीय मद में दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17-11-2015 को प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के निगरानी की ग्राह्यत पर तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में तथा अवधि विधान की धारा-5 में अंकित किये हैं। अनावेदक शासकीय अभिभाषक ने दिनांक 22-5-14 के आदेश के विरुद्ध 17-11-15 को प्रस्तुत विलम्ब का प्रत्येक दिन का कारण स्पष्ट न करना बताते हुये निगरानी अवधि-वाह्य होने से निरस्त करने की मांग रखी।

9



5/ अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर शिवपुरी का आदेश दिनांक 26-5-14 को पारित हुआ है आदेश की जानकारी विलम्ब से दिनांक 1-8-15 को प्राप्त होना बताया है परन्तु उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त यदि 1-8-15 को जानकारी हुई तो 7-8-15 को नकल हेतु आवेदन देना तथा 14-8-15 को नकल प्राप्त होने पर भी 17-11-15 को निगरानी प्रस्तुत करने का भी बौधानिक कारण नहीं है। जानकारी के दिन से निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब इसलिये क्षमा योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक को अपर कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 26-5-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि 7-8-15 को आवेदन देने पर दिनांक 14-8-15 को प्राप्त हो चुकी है और 14-8-15 से निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 17-11-2015 के बीच की अवधि 3 माह से अधिक समय के दिन-प्रतिदिन का हिसाब आवेदक के अभिभाषक नहीं दे सके एवं अन्य प्रकार से समाधान भी नहीं करा सके। अतएव निगरानी अवधि-वाह्य प्रस्तुत होने के कारण अग्राह्य की जाती है।



(डॉ० मधु खरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर